रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-613/2026/2296/22-02-2025-17(1412)/2023

लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी सं0-949/2023) पुत्र श्री किशनलाल, ऊतरा, थाना-सासनी, जनपद-अलीगढ़ वर्तमान जनपद-हाथरस का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-94/1982 में धारा-148, 302/149 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 15.06.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.04.2008 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 02 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट हाथरस के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या- 613/2026/2296(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस

3- पुलिस अधीक्षक, हाथरस

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार इटावा।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि0मि0रिट संख्या-19056/2025 चन्द्रपाल बनाम उ0प्र0राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 के सन्दर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in